International Journal of Education and Science Research Review
Volume-1, Issue-1 February 2014 ISSN 2348-6457

शिक्षा के क्षेत्र में मुक्त-विश्वविद्यालयों का योगदानः-एक अध्ययन

तपेन्द्र कुमार चौधरी
शोधार्थी
(एम.ए.,एम.एड.)
अ.प्र.सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म0प्र0)

प्रस्तावना :-

भारत की निवर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने शिक्षा के लोकतन्त्रिकरण की अवधारणा को विकसित करते हुए कहा किः- ''शिक्षा मानव को बन्धनों से मुक्त करती है। और आज के युग में तो यह लोकतन्त्र की भावना का आधार भी है। जन्म तथा अन्य कारणों से उत्पन्न जाति एंव वर्गगत **विषमताओं** को दूर करते हुए **मनुष्य** को इन सबसे ऊपर उठाती है।''

देश में नियमित शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है कि आम आदमी के लिए शिक्षा पाना लोहे के चने चबाना है। स्कूल-कॉलेजों में तो शिक्षा नाममात्र रह गयी है आज देश में डिग्रियाँ तो मिल सकती हैं मगर उच्च शिक्षा बिल्कुल नहीं। इस कारण ज्यादातर विद्यार्थी कोचिंग ज्वाइन करने को मजबूर रहते है परन्तु गरीब विद्यार्थी धन के अभाव के कारण अपनी शिक्षा पूरी नही कर पाते हैं, दूसरे आज कल व्यावसायिक कार्यक्रमों का दौर चल रहा है जो कि अत्याधिक महँगें होने कारण कुछ विशेष वर्ग तक ही सीमित हैं। ऐसी स्थिति में मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूरस्थ शिक्षा संस्थान नियमित शिक्षा के पर्याय के रूप में मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूरस्थ शिक्षा संस्थान नियमित शिक्षा के पूरक के रूप में समाज के सभी वर्गो को शिक्षा प्रदान कर रही है। क्योंकि भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या को नियमित शिक्षा के माध्यम से शिक्षा प्रदान कर पाना असम्भव ही नहीं अपितु कल्पनाशील है।

किसी भी **राष्ट्र** के विकास में शिक्षा एक सफल तथा प्रभावकारी साधन है इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के उपबन्ध 'क' में शिक्षा को एक मूल अधिकार प्रदान करते हुए सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था की गयी। जिसके तहत समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सम्पूर्ण **राष्ट्र** में अनेकों प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों के साथ-साथ विभिन्न केन्द्रीय तथा राजकीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की गयी। किन्तु भारत जैसे विशाल जनसंख वाले **राष्ट्र** में समाज के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करना कोई सरल कार्य नहीं था। शीघ्र ही इस बात की आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि मात्र स्कूलों, कालेजों या विश्वविद्यालयों की स्थापना करके नियमित शिक्षा द्वारा समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षित नहीं किया जा सकता। जिसके परिणमस्वरूप दूरस्थ एवं शिक्षा का प्रयोग एवं विकास किया। मुक्त विश्वविद्यालय की कल्पना ब्रिटेन से ली गई जहाँ विश्व का पहला मुक्त विश्वविद्यालय सन् 1969 में स्थापित किया गया। सन् 1971 में इसमें विद्यार्थियों का प्रवेश आरम्भ होगा। इसकी सबसे अधिक उपयोगिता पारिवारिक महिलाओं, टैक्सी चालकों, उद्योग और कृषि में लगे कामगार, जेल में बन्द अपराधियों तथा उन लोगों के लिए है जो किसी कारणवश उच्च शिक्षा की औपचारिक धारा से मध्य में अलग हो जाते हैं या किसी अन्य कारण से उच्च शिक्षा से बिल्कुल वंचित रह जाते है। वे लोग दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने पश्चात् रोजगार तथा अन्य अवसर प्राप्त करते है।

भारत में मुक्त विश्वविद्यालय के स्थापना की पेशकश सन् 1970 से चल रही है, भारत के शिक्षा मन्त्राल ने ब्रिटेन के मुक्त विश्वविद्यालय से तीन विशे-ज्ञों को नई दिल्ली में हुई एक गो-ठी में आमन्त्रित किया। इस गो-ठी से यह **निष्कर्ष** निकला कि भारत को ब्रिटेन की भाँति एक मुक्त विश्वविद्यालय की आवश्यकता है। परिणामस्वरूप भारत सरकार ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के कुलपति प्रोफेसर जी पार्थसारथी की अध्यक्षा में 1971 में भारत में दूरस्थ शिक्षा के विकास हेतु एक कार्यकारी समूह गठित किया गया जिसने अपनी रिपोर्ट 1975 में दी तथा दूरस्थ शिक्षा कि वकालत की तत्पश्चात् 1982 में माधुरीशाह समिति ने भी **राष्ट्रीय** मुक्त विश्वविद्यालय के सृजन हेतु व्यवहारिक कदम उठाने की सिफारिश की परन्तु इससे पहले ही भारत में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से सन 1961 में दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्नातक कक्षाओं के लिए पत्राचार पाठयक्रम प्रारम्भ कर दिए गये थे। तत्पश्चात् 22 अगस्त 1982 को आन्ध्रप्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई जो वर्तमान में डॉ. भीम राव अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय (BRAOU) के नाम जाना जता है। इसके उपरान्त कोटा मुक्त विश्वविद्यालय, राजस्थान (KOU)

तथा यशवन्त राव चव्हाण **महाराष्ट्र** मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक (YCMOU) और नालन्दा मुक्त विश्वविद्यालय, पटना की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश और कर्नाटक ने भी मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना कर ली है। इसके उपरान्त विभिन्न राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। इन राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त सन् 1985 में स्वा. इन्द्रिरा गॉधी की जन्म-तिथि 19 नवम्बर से इन्द्रिरा गॉधी **राष्ट्रीय** मुक्त विश्वविद्यायल (IGNOU) का श्री गणेश हुआ। वर्तमान में कुल एक **राष्ट्रीय** मुक्त विश्वविद्यायल, 14 राज्य मुक्त विश्वविद्यालय तथा 204 दूरस्थ शिक्षा संस्थान, आवश्यकता एवं रोजगार परख शिक्षा अति अल्पशुल्क में प्रदान कर रहे है। दूरस्थ संस्थानों एवं मुक्त विश्वविद्यालयों के उद्देश्य निम्न थे-

1. जनसंख्या के उन भागो में उच्च शिक्षा सुलभ कराने की व्यवस्था करना जो इन सुविधाओं से वंचित हो। पिछड़े क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले छात्रों, गृहणियों आदि जैसे **विशिष्ट** लक्षित वर्गो के लिए उच्चतर शिक्षा के विशे-ा कार्यक्रम प्रारम्भ कर शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाना।
2. लोगों को उनके घरों पर या उनके कार्य स्थल पर सुविधाजनक सम पर शैक्षिक सुविधाऐं प्रदान करना। विश्वविद्यालयी कक्षाओं के स्थान पर घर पर अध्ययन की व्यवस्था करना और विद्यार्थी को अपनी गति से पाठ्यक्रम पूरा करने की सुविधा देना। इस प्रकार परम्परागत विश्वविद्यालयों की भीड़ को कम करना।
3. विद्यार्थी को एक साथ कमाने और पढ़ने की स्थिति प्रदान करना।
4. आधुनिकतम संचार व्यवस्था द्वारा ज्ञान का प्रसार करना। पत्राचार पाठ्यक्रम सहित सुदूर शिक्षण के स्तरों की ज्ञात कराना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना।
5. ज्ञान की विधि, दुर्लभ तथा व्यापारपरक शाखाओं में लोगों को प्रशिक्षित करना जिससे देश की अर्थव्यवस्था प्राकृतिक और मानव संसाधनों के आधार पर हो।
6. ज्ञान और कुशलता बढ़ाने हेतु सतत् शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करना।

वर्तमान में भारत में कुल 14 राज्य स्तर पर तथा एक **राष्ट्रीय** स्तर पर मुक्त विश्वविद्यालय है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट**-1 में है।

वास्तव में मुक्त विश्वविद्यालय का उद्देश्य वर्तमान औपचाारिक विश्वविद्यालयी शिक्षा की व्यवस्था का एक विकल्प के रूप में कार्य करना तथा बहुसंख्यक देशवासियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विकसित करना है जो औपचारिक शिक्षा से इसलिए वंचित रह जाते हैं या बीच में ही छोड़ देते हैं या बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उस व्यवस्था में प्रवेश नियमों, आयु सीमा, उपस्थिति तथा ौक्षिक कार्यक्रमों में प्रचालन (Operation) के कठोर (Rigid) बन्धन हैं। कुछ बालिकाएँ और घरेलू महिलाएँ सामाजिक बन्धनों के कारण भी उच्च शिक्षा की औपचारिक ाखा से लाभान्वित नहीं हो पातीं। उन सब के लिए भी मुक्त विश्वविद्यालय द्वितीय अवसर (Second chance) प्रदान करता है।

सभी राज्यों में स्वयं के मुक्त विश्वविद्यालय नहीं है। उत्तर प्रदेश का राज्य मुक्त विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश **राजर्षि** टंडन मुक्त विश्वविद्यालय (UPRTOU) है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश **राजर्षि** टंडन मुक्त विश्वविद्यालय (UPRTOU) तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में इन्दिरा गॉधी **राष्ट्रीय** मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) अपने क्षेत्रीय केन्द्रों एवं अध्ययन केन्द्रों के माध्यम से राज्य के स्लम एवं दूरदराज के अछूते रहने वाले एक बड़े समूह को उच्च शिक्षा पहुँचा रहे है। दोनों मुक्त विश्वविद्यालय गाँव के कामगार, गृहणियों एवं शालात्यागी विद्यार्थियों को रोजगार परक एवं व्यवहारिक शिक्षरा प्रदान कर रहे है।

देश भर में औपचारिक शिक्षण प्रणाली के तहत 400 से अधिक नियमित विश्वविद्यालयों तथा 22,000 कॉलेजों में पोस्ट-सेकेंन्ड्री स्तर पर देश के कुल छात्रों का 76 प्रतिशत भाग शिक्षा प्राप्त करता है। इसके मुकाबले उच्चतर शिक्षण के लिए पात्र कुल छात्रों की जनसंख्या की शिक्षण की जरूरतो का 24 प्रतिशत भाग दूरस्थ शिक्षण प्रणाली पूरा करती है। और यह सब मात्र करीब 207 परंपरागत विश्वविद्यालायों में भी मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण (ओ.डी.एल.) प्रणाली की व्यवस्था है जिसके द्वारा भी छात्र लाभान्वित हो रहे है। **वर्षो** से देश जिन सर्वोच्च चुनौतियों का सामना कर रहा है उनमें देश के हर कोने में 116 करोड़ लोगों को साक्षर बनाने का काम भी शामिल है। हमारी वर्तमान 64.5: की साक्षरता की दर बहुत अच्छी तो कही जा सकती है लेकिन एक पुरानी गिलास की आधा भरा या आधा खाली की कहानी की तरह में निश्चत तौर पर आधा खाली की तरफ डाटा रहना उचित है। इसके अलावा हमारी मात्र 13 प्रतिशत वयस्क और पात्र जनसंख्या ही उच्चतर शिक्षण संस्थानों में पहुँच पाती है जबकि इसकी तुलना में विकसित देशों की जनसंख्या के आंकड़े बहुत अधिक है। इसके अतिरिक्त वहां स्कूल स्तर पर शिक्षण कार्य के लिए शिक्षण के क्षेत्र में उपयुक्त डिग्रीधारी शिक्षकों की उपलब्धता भी काफी अधिक होती है। यह भी सही है कि शिक्षण संस्थान में अध्ययन के लिए पात्र जनसंख्या (स्कूल या उच्चतर अध्ययन हेतु) आज भारतीय स्कूल प्रणाली के अंतर्गत तीन से चार मिलियन प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता है जो कि सामान्य स्थितियों में शामिल

करना एक असंभव काम प्रतीत होता है। अतः सोचना यह है कि क्या इन सब कठिनाइयों का विकल्प के रूप में इस समय दूरस्थ शिक्षण प्रणाली ही अधिकतर समस्याओं के हल के लिए लाभदायक और प्रभावकारी औजार काम कर सकता है।

मुक्त विश्वविद्यालय में मुक्तशब्द इसलिए जोड़ा गया क्योंकि इस नई और उभरती शिक्षा प्रणाली ने लोगों के लिए कुछ मौलिक स्तर क तैयारियों के साथ ही बगैर किसी बेसिक योग्यता के ही उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराने के अवसर दिए। विभिन्न पाठ्यक्रमों के चयन में लचीलेपन तथा अच्छे दूरस्थ एवं मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण प्रणाली संस्थानों से टेलर-मेड तथा संक्षिप्त अध्ययन सामग्री की उपलब्धता ने पूरे विश्व में कहीं भी लोगों को अधिक से अधिक संख्या में इससे जोड़ दिया है।

इस प्रकार कह सकते है कि भारत का औपचारिक शिक्षा क्षेत्र छः दशके से अधिक समय के दौरान भी अपेक्षित काम नहीं कर पाया है। ऐसी स्थिति में दूरस्थ शिक्षण प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसके जरिए आने वाले दिनों में अधिकतम साक्षरता हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। वित्तीय या अन्य कई कारणों से कई लोगों को किसी रोजगार से जुड़ना पड़ता है या किसी संस्थान में औपचारिक अध्ययन को पीछे छोड़ते हुए व्यवसायिक गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों का निश्चित रूप से उच्चतर शिक्षा प्राप्ति की अपनी इच्छाओं को पूरा करने के वास्ते खोए हुए अवसरों को पुनः पाने का मन परूर होगा। बहुत से लोग ऐसा अपनी जिज्ञासा के वश भी करना चाहते होंगे। इसी तरह बहुत से कामकाजी व्यक्ति या व्यवसाय में पहले से जुड़े लोग दूरस्थ शिक्षण प्रणाली के जरिए अपनी व्यावसायिक क्षमता में विस्तार कर सकते है। दूरस्थ शिक्षण शिक्षण प्रणाली उनके लिए सदैव कहीं भी सामान्यतः इस तरह निर्धारित किया जाता है कि ये हर किसी की जेब पर भारी न पड़े। व्यावसायिक आवश्यकता, सुविधा, कौशल वृद्धि के लिए कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद से विभिन्न पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर सकता है।

दूरस्थ शिक्षण प्रणाली में मॉड्यूलर पद्धति में पाठ्यक्रमों को डिजाइन किया जाता है (जहॉ कहीं लागू है) और एक **वर्ष** से अधिक की अवधि के पाठ्यक्रमों को कुछ इस प्रकार तैयार किया जाता है कि यदि कोई छात्र कुछ के पेपरों को भी पूरा कर लेता है और उनमें सफल हो जाता है तो प्रमाण-पत्र या डिप्लोमा आदि प्रदान कर दिया जाता है, यदि कोई व्यक्ति पाठ्यक्रमो का अध्ययन जारी रखता है तथा इसे सफलतापूर्वक पूरा करता है तो उसे पूर्ण पाठ्यक्रम प्रमाण-पत्र प्रदान किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कुछ विश्वविद्यालय जनसंचार में दो **वर्षीय** मास्टर डिग्री कार्यक्रम संचालित करते हैं। जो छात्र एक **वर्ष** सफलापूर्वक पूरा कर लेता है तो उसे डिप्लोमा प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है तथा यदि वह सफलतापूर्वक अंतिम व-र्ा की पढ़ाई पूरी कर लेता है तो उसे पूर्ण मास्टर डिग्री प्रदान की जाती है। मॉड्यूलर पद्धति दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षण की मूलभूत **विशेषता** है। पूरे विश्व में लचीलापन, सुविधा और सेवा दूरस्थ शिक्षण प्रणाली के प्रमुख **शीर्ष** बिन्दु है। चूँकि प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन सामग्री सुगठित रूप में तैयार की जाती है अतः वह सदैव संक्षिप्त, बिन्दुवार, समग्र और पढ़ने में गठन की आवश्यकता है जो नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा दे सके और बढ़ोती अर्थव्यवस्था की कौशल आवश्यकताओं को पूरा कर सके। वर्तमान में भारत में बच्चों या फिर बीच में ही पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती है। **राष्ट्रीय** ज्ञान आयोग ने शिक्षा का विद्यालयीय शिक्षा प्रणाली में पीढ़ीगत परिवर्तन लाए जाने की सिफारिश की है। तथा **घोषणा** की है एक ऐसी समावेशी शिक्षा प्रणाली लानी होगी कि कोई भी इसकी परिधि से बाहर नहीं रह सके।

आज इस बात को लेकर चिंता बढ़ रही है कि शिक्षा प्रणाली कुशल और रोजगार के लिए तैयार जनशक्ति का निर्माण करने की अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा रही है, जिसके कारण कौशल संबंधी बाजार की आवश्यकताओं और रोजगार चाहने वालों के कौशल के बीच खाई बढ़ती जा रही है। यदि एक छात्र, शिक्षक या शोधार्थी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की खामियों से नाखुश हैं, और उन्हें कॉलेज और विश्वविद्यालय में नियम-कानूनों में बांधकर, वि-ार्यों के पिंजड़ों, में कैद कर दिया गया है, लेकिन वे सभी सृजानात्मक के पंख लगाकर अपने अध्ययन और शोध की गहराइयों में गोते लगाना चाहते हैं तो दूरस्थ शिक्षा में सबके सामने उम्मीदें है। जहॉ न कोई दीवार होगी, न बेड़ियां होंगी, विद्यार्थी जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहेंगे, उनके विचारों को सही दिशा में आगे बढ़ना चाहेंगे, उनके विचारों को सही दिशा मिल सकेगी।

वर्तमान में देश के लगभग सभी बुद्धिजीवी इस बात पर सहमत हैं कि इस शिक्षा प्रणाली के तत्काल बदलने की आवश्यकता है। अगर 12वीं सदी में भारत के 6 से 14 **वर्ष** के छह करोड़ बच्चे अशिक्षित रहते हैं और बेरोजगारों और अर्ध-बेरोजगारों की फौज बढ़ती है, तो यह गहन चिंता का वि-ाय है। देश में एक ओर कौशल सम्पन्न लोगों की भारी कमी महसूस की जा रही है और दूसरी ओर बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हैं। संक्षिप्त में कहा जा सकता है कि मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली (ओडीएल) औपचारिक शिक्षा का सबसे अधिक सशक्त और आधुनिक विकल्प के रूप में उभर रहा है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. कपिल डॉ.एच.के., (1991): अनुसंधान की विधियं, कचहरी घाट आगरा 1991
2. **सुभाष कश्यप** (1991): हमारा संविधान, पेज 102, नेशनल बुक ट्रस्ट, इण्डिया 1992
3. सिंह रोजन्द्र पाल, (1991): भारतीय आधुनिक शिक्षा **वर्ष** 9 तृतीय 1992 पेज, 46
4. जैन अलका (1996): अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों की बालकेन्द्रित शिक्षण के प्रति अभिवत्ति एवं उनकी समस्याओं का अध्ययन, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, अजमेंर (राज.)
5. पांडेय रामकशल (1997): भारतीय शिक्षा की समसामयिक समस्याएं, पांडेय रामशकल, पेज 233, 1997
6. आर.ए. शर्मा (1997): शिक्षा अनुसंधा, पेज 121, सूर्या पब्लिकेशन, मेरठ 1997
7. दिलीप कुमार ''खामोश'' (2008): पाठक नामा, दैनिक जागरण, 19 दिसम्बर 2008
8. इग्नू (2011): विद्यार्थी पुस्तिका एवं विवरणिका, 2011 इग्नू मैदान गढ़ी, नई दिल्ली